types of family oriented projects to be implemented in a most effective manner; and

14. A new system of concurrent evaluation on the basis of taking up 36 districts, 72 blocks and a group of 10 current beneficiaries and 10 beneficiaries who received their assistance two years ago, per month has been introduced to have a closer monitoring of the programme.

FAO recommendations for price incentives

*247. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the FAO experts have recently suggested that India must give appropriate price incentives to its farmers to raise agricultural production;

(b) whether they have also stated that if adequate price and market is assured to the farmers, abundant production of crops is possible;

(c) if so, what are the other suggestions made by the FAO experts and whether Government have examined those suggestions; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): (a) and (b) No, Sir. No such suggestions have been made to the Government of India by any FAO experts.

(c) and (d) Do not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं में विद्यार्थियों को हटा कर भूतपूर्व सैनिकों का लगाया जाना

*248. **श्री सूरज प्रसाद :**
श्री जे० पी० गोयल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना (डी० एम० एस०) का दुग्ध-वितरण संबंधी कार्य अनेक वर्षों से विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रत्येक डिपो पर वरिष्ठ और कनिष्ठ डिपो अभिकर्ताओं के रूप में तैनात विद्यार्थियों को प्रति माह क्रमश: 180 रुपये और 120 रुपए का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन विद्यार्थियों के स्थान पर भूतपूर्व सैनिकों को कमीशन के आधार पर लगाने का निर्णय किया है, जिसके फलस्वरूप निर्धन परिवारों के इन विद्यार्थियों को अपने शिक्षा-संबंधी खर्चे पूरे करने में अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन भूतपूर्व सैनिकों को, उन्हें इन दूध के डिपुओं का आवंटन करने के बजाय किन्हीं स्थायी पदों पर नियुक्त करने का विचार रखती है, क्योंकि इन डिपुओं से उन्हें प्रतिमाह 180 रुपए या 240 रुपए की आय ही होगी जो कि उनके लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी; और

(घ) क्या इन डिपुओं पर कार्यरत विद्यार्थियों ने इस संबंध में सरकार को कोई विरोध-पत्र प्रस्तुत किया है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी, हां। वरिष्ठ डिपो एजेंटों के रूप में तैनात विद्यार्थियों को 6 रुपए प्रति दिन प्रति ड्यूटी और डिपो एजेंटों को 4 रुपए प्रति दिन प्रति ड्यूटी के हिसाब से अदायगी की जाती है।

(ख) यह फैसला किया गया है कि चरणबद्ध पद्धति से डिपो एजेंटों के स्थान पर धीरे-धीरे भूतपूर्व सैनिकों को रखा जाए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था से दूध का अधिक लम्बी अवधि तक बिक्री के लिए उपलब्ध होना सुनिश्चित हो जाएगा। बिक्री से अर्जित धन को क्रास्ड चैकों द्वारा एकत्र करना सरल हो जाएगा

और दूध की भरी हुई और खाली बोतलें देना और लेना आदि सुविधाजनक हो जाएगा। तथापि, गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को अपने शिक्षा संबंधी खर्चे सहन करने में आ रही मुश्किलों को कम करने की दृष्टि से इस योजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए ग्राहियों के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके बाद यदि सेवा संतोषजनक हो, तो दिल्ली दुग्ध योजना के साथ उनके लम्बी अवधि के करार का नवीकरण किया जाता है। उन्हें पहले 500 लीटर तक दूध की बिक्री के लिए 5 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से कमीशन दिया जाता है, और उसके बाद प्रतिदिन 500 लीटर से अधिक दूध पर 3 पैसे प्रति लीटर दिए जाते हैं।

(घ) कुछ विद्यार्थियों ने भूतपूर्व सैनिकों को ग्राहियों के रूप में नियुक्त किए जाने के खिलाफ अभ्यावेदन दिया है। सच्चे मामलों में मुश्किलों को कम करने की दृष्टि से यह योजना धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जाएगी।

Discriminatory distribution of flood relief in Assam

*250. SHRI KAMALENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have received any information to the effect that the Government of Assam have followed discriminatory policy in the distribution of flood relief materials during the year 1986 and that they have not adhered to the stipulated norms while giving financial assistance to the affected families;

(b) if so, what action Central Government have taken in this regard; and

(c) whether the Government of Assam have submitted the accounts of expenditure of the central assistance provided to help the flood victims during the year 1986?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): (a) and (b) Some complaints have been received that assistance for fully damaged and partially damaged houses has not been given as per Central Government's norms. The matter is being examined in consultation with the Government of Assam. However, it needs to be clarified that the Central Government norm represents a ceiling for Central assistance and State Governments are competent to distribute assistance at a lower rate if the nature of the damage or availability of funds so warrants.

(c) Yes, Sir. Expenditure statement in respect of Central assistance sanctioned for the year 1985-86 has been received from the Government of Assam.

Installation of statues of national leaders in Delhi

*251. SHRI KALPNATH RAI:
SHRI RAFIQUE ALAM:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the names of places where the statues of national leaders have been installed in Delhi so far;

(b) what are the names of the national leaders whose statues are likely to be installed in Delhi in the near future and the places identified for the purpose;

(c) whether the statue of Mahatma Gandhi is proposed to be installed in the vicinity of India Gate; if so, by when and if not, what alternative location has been earmarked for the statue of Mahatma Gandhi in Delhi and by when it is likely to be installed; and